संपादकीय

सच की चाहत तो बहुत, बर्दाश्त जरा भी नहीं...

केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने सुझाया है कि स्कूली किताबों में आपातकाल के इतिहास पर एक अध्याय जोड़ना चाहिए ताकि बच्चों को उस दौर की जानकारी हो सके। उनका कहना इस मायने में तो सही है कि योरप का इतिहास और जर्मनी का इतिहास, मुगलों का इतिहास और अंग्रेजों का इतिहास तो स्कूल-कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत का ताजा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। उनका सुझाव एक साहसी सोच है, और हम इस बात के हिमायती हैं, हालांकि ताजा इतिहास को छूना कितना खतरनाक हो सकता है, उसे पहले सोच लेना चाहिए।

अब पौन सदी पहले का इतिहास गांधी की हत्या है, उसे स्कूली पाठ्यक्रम में किस तरह पढ़ाया जाएगा? देश की आम जनता और दूसरी तरफ गोडसेवादियों की सोच और नजरिए में बड़ा फर्क है। गांधी की हत्या को एक राष्ट्रवादी काम कहा जाएगा, या कि देश के खिलाफ की गई हत्या? क्या सरकारों में इतना हौसला होगा कि गोडसे को खुलकर देख सकें, और दिखा सकें? इसके बाद अगर देखें तो आपातकाल तो आता ही है, 1984 के सिख विरोधी दंगे भी आते हैं। इन दंगों के पहले का स्वर्ण मंदिर का आतंकियों का डेरा भी आता है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी। हौसले के साथ खरा इतिहास लिखने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन किस सरकार में यह हौसला होगा कि केन्द्र या राज्य की स्कूली किताबों में इस पूरे दौर को ईमानदारी से खुलकर लिख सके? थोड़ा और आगे बढ़ें तो भारत के ताजा इतिहास में बाबरी मस्जिद को गिराना भी आता है, बाबरी के ठीक पहले अडवानी की रथयात्रा भी आती है, और बाबरी के ठीक बाद मुंबई के बम धमाके भी आते हैं। अब इनको किस इतिहासकार की नजर से दिखाया जाएगा? थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो गोधरा कांड और गुजरात के दंगे आते हैं, और क्या आज सरकार ईमानदारी के साथ इस दौर को स्कूली बच्चों के सामने रख सकेगी?

सच की मांग तो आसान होती है, सच की चाहत भी जायज होती है, लेकिन सच के लिए बर्दाश्त कम ही लोगों के दिल-दिमाग में होता है। ताजा इतिहास तो मधुमक्खियों के छत्ते सरीखा होता है जिसे छेड़ना कम खतरनाक नहीं होता। लोगों को याद होगा कि कुछ लोग अपने लिखे हुए दस्तावेज की शर्त के साथ छोड़कर जाते हैं कि उन्हें उनके मरने के बाद जारी किया जाए, या कि बीस बरस बाद जारी किया जाए। लोगों के मन में ताजा इतिहास की ईमानदारी के लिए कोई बर्दाश्त नहीं रहता, आज तो भारत में बनने वाली फिल्मों में किसी राजा या रानी के जिक्र को लेकर बवाल खड़ा हो जाता है कि उनमें ऐतिहासिक सच्चाई को तोड़ा-मरोड़ा गया है। इसलिए वेंकैया नायडू की बात अच्छी होते हुए भी इस देश के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इस देश ने सच लिखने, कहने, और सुनने का हक खो दिया है। अब तो इस देश में बिल्कुल पुख्ता और निर्विवाद इतिहास को भी क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड की लिखावट की तरह मिटाना शुरू हो गया है, और संग्रहालयों पर हमले होने लगे हैं, दस्तावेजों को जलाया जाने लगा है, और इतिहासकारों को पीटा जाने लगा है। ऐसा देश बच्चों को कहां से लाकर सच पढ़ाएगा? जर्मनी के हिटलर के इतिहास, या कि अमरीका के अश्वेतों के इतिहास, या योरप के इतिहास को पढ़ाना ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि उसमें किताबों को लिखने वालों को मारने के लिए किसी अमरीकी या यूरोपियन की आत्मा नहीं आ सकती, और न ही उनके भक्तजन मारने के लिए आ सकते हैं। अपना खुद का इतिहास बड़ा घातक और जानलेवा साबित हो सकता है, अगर वह सच हो तो। इस देश में आज पाखंड की पूजा होती है, और हकीकत की हिकारत। ऐसे में ताजा इतिहास के सच की ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, मतदाताओं के बीच चुनाव लड़ने जाने वाले नेता और उनकी पार्टियां शायद ही किसी सच को बर्दाश्त कर सकें।

एक ग़ज़ल गुनगुनाएं

दूर से ही बस दरिया-दरिया लगता है
डूब के देखो कितना प्यासा लगता है

तन्हा हो तो घबराया सा लगता है
भीड़ में उस को देख के अच्छा लगता है

आज ये है कल और यहाँ होगा कोई
सोचो तो सब खेल-तमाशा लगता है

मैं ही न मानूँ मेरे बिखरने में वर्ना
दुनिया भर को हाथ तुम्हारा लगता है

ज़ेहन से काग़ज़ पर तस्वीर उतरते ही
एक मुसव्विर कितना अकेला लगता है

प्यार के इस नशा को कोई क्या समझे
ठोकर में जब सारा ज़माना लगता है

भीड़ में रह कर अपना भी कब रह पाता
चाँद अकेला है तो सब का लगता है

शाख़ पे बैठी भोली-भाली इक चिड़िया
क्या जाने उस पर भी निशाना लगता है।

-वसीम बरेलवी

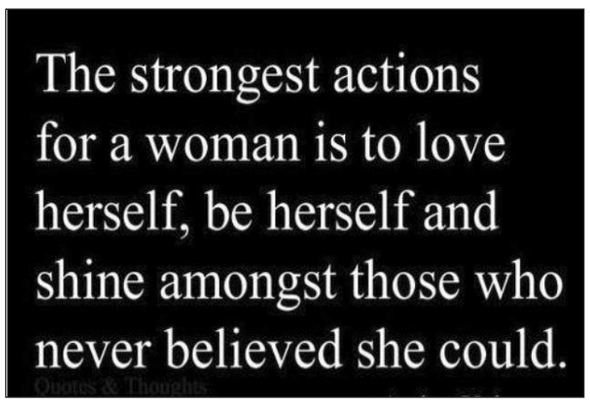

किसानों की आत्महत्याएं

■ प्रभाकर

तमाम वादों और उपायों के बावजूद भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों की आत्महत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्जमाफी की मांग में तमिलनाडु के सैकड़ों किसानों ने बीते अप्रैल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना कपड़ों के धरना-प्रदर्शन किया था। केंद्र सरकार ने इस मामले में साफ पल्ला झाड़ लिया है। उसका कहना है कि राज्य सरकारें अपने खजाने से किसानों की कर्ज माफी का फैसला कर सकती हैं। केंद्र इस मामले में कोई सहायता नहीं करेगा। दूसरी ओर बहुत से विशेषज्ञ आत्महत्याओं के मौजूदा दौर के लिए नोटबंदी को प्रमुख वजह मानते हैं।

केंद्र सरकार के तमाम वादों के बावजूद देश में किसानों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी राज्य से किसनों के मरने की खबरें आ रही हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में किसानों के हिंसक प्रदर्शन में कम से कम आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। हालात संभालने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी किसानों के कर्ज माफ करने का एलान किया है। इस साल देश के विभिन्न हिस्सों में बंपर फसल होने की वजह से किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इससे उनकी लागत कर वसूल नहीं हो पा रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों किसानों के कर्ज माफ करने का एलान किया। इससे सरकारी खजाने पर 36 हजार करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इसी तरह पंजाब सरकार ने दो लाख छोटे व मझौले किसानों के 24 हजार करोड़ के कर्ज माफ करने का एलान किया। उनसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों की हड़ताल के बाद हजारों करोड़ की कर्ज माफी का फैसला किया था। उसके बाद अब इस सप्ताह कर्नाटक सरकार ने 22 लाख छोटे किसानों के 8,165 करोड़ के कर्ज माफ करने का फैसला किया है। यह कर्ज सहकारिता बैंकों से लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कहते हैं कि किसानों को असली फायदा तब होगा जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से ऐसी पहल की जाए। उन्होंने प्रदेश बीजेपी से कहा है कि वह केंद्र को इसके लिए राजी करवाये। फिलहाल राज्य के किसानों पर सरकारी बैंकों का 42 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है।

अब इसके बाद हरियाणा व गुजरात के किसानों ने भी कर्जमाफी की मांग तेज कर दी है। एक निजी संस्था इंडिया स्पेंड ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि मार्च, 2017 तक बीते नौ वर्षों के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों ने 4.80 करोड़ किसानों के लगभग 89 हजार करोड़ (13.9 अरब अमेरिकी डालर) का कर्ज माफ कर दिया। सरकारें किसानों की आत्महत्या रोकने की दलील देकर कर्ज माफी का एलान कर रही हैं। देश में किसानों का कर्ज माफ करने का सिलसिला वर्ष 1990 में वीपी सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने किया था। तब एकमुश्त 10 हजार करोड़ के कर्ज माफ किए गए थे।

> हाल में कुछ राज्यों ने हजारों करोड़ के कर्ज माफ जरूर कर दिए हैं। लेकिन इससे हालात में ज्यादा अंतर नहीं नजर आ रहा है। भारत में हर साल दस हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं।

कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि कर्ज माफी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्जमाफी के इस तेज होते सिलसिले का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा कर्ज इन बैंकों से ही मिला है। अब बड़े पैमाने पर होने वाली कर्जमाफी से इनका एनपीए (नान-परफार्मिंग एसेट) तेजी से बढ़ेगा। सरकारी खर्चों पर निगाह रखने वाली संस्था इंडिया स्पेंड का कहना है कि देश के आठ राज्यों के किसान कुल 3.1 लाख करोड़ का कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं। यह देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 फीसदी है। अमूमन सरकारें किसानों की आत्महत्याओं पर अंकुश लगाने की दलील देकर कर्ज माफ करने का फैसला करती हैं। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के हवाले बताते हैं कि बीते 21 वर्षों में 3.18 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यानी हर 41 मिनट पर एक किसान ने आत्महत्या की।

कर्जमाफी से समस्या स्थायी रूप से न सुधरने की एक वजह यह भी है कि ज्यादातर किसान ग्रामीण स्तर पर स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेते हैं। इसलिए कर्जमाफी का असली फायदा उनको नहीं मिल पाता। आंकड़ों के मुताबिक, देश के 32.5 फीसदी यानी लगभग आठ करोड़ छोटे व मझौले किसान स्थानीय साहूकारों से ही कर्ज लेते हैं। इससे साफ है कि कर्ज माफ होने की स्थिति में ऐसे महज दस करोड़ किसानों को ही लाभ होगा। मोरगन स्टेनले ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कर्ज माफ करने के बाद सरकारें संबंधित बैंकों को उस रकम का भुगतान करती हैं। लेकिन इससे धीरे-धीरे कर्ज की संस्कृति खत्म होने लगती है और दूसरे किसान भी जानबूझ कर कर्जों का भुगतान नहीं करते। इससे राज्य सरकार के संसाधनों पर भी भारी असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के मामले में उसका राजस्व घाटा बढ़ कर सकल घरेलू उत्पाद के 2.71 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कर्जमाफी की राह को फिसलनभरी करार देते हुए राज्य सरकारों से बहुत सोच-समझ कर यह राह चुनने की सलाह दी है। पटेल कहते हैं, कर्जमाफी एक अस्थायी समाधान है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और बैंकों के एनपीए पर गहरा असर पड़ेगा। साथ ही राज्यों की ओर से बीते कुछ वर्षों के दौरान की गई प्रगति पर पानी फिर सकता है।

ग्रामीण मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार पी। साईंनाथ कहते हैं, कृषि क्षेत्र पर गहराते गंभीर संकट की अनदेखी कर किसानों की आत्महत्या पर अंकुश लगाने का प्रयास तमाम नलों को खुले छोड़ कर फर्श को सुखाने के लिए पोंछा लगाने की तरह है। वह कहते हैं कि इससे तात्कालिक राहत तो मिल सकती है, लेकिन समस्या हल नहीं हो सकती। सरकार को समस्या की जड़ तक पहुंच कर नीतियों में संशोधन के जरिए इस पर काबू पाने की पहल करनी चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा परिस्थिति नीतिगत खामियों और बरसों से कृषि क्षेत्र की अनदेखी का नतीजा है। देश में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन ने हाल में अपने एक लेख में कहा था कि खराब मानसून और खरीद मूल्यों में कमी की वजह से ही किसान कर्ज के ऐसे जाल में फंसते जाते हैं जिससे वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। वह कहते हैं, कर्जमाफी जैसी आसान राह चुनने की बजाय सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालीन सुरक्षित कर्ज प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

कृषि विशेषज्ञों ने बीते साल नवंबर में हुई नोटबंदी को भी इस समस्या की गंभीरता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर, 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को लागू कर कृषि क्षेत्र की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन वर्ष 2006 में सौंपी गई आयोग की सिफारिशें अब तक फाइलों में ही धूल फांक रही हैं। ऐसे में मौजूदा समस्या के समाधान के आसार कम ही हैं। http://www.dw.com/

देश और दुनिया की इस हफ्ते

■ प्रकाश दुबे

राम-राम

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में रोज़ा इफ्तारी की परंपरा बंद कराई। भरे पेट वाले अति विशिष्ट मेहमानों को सरकारी खजाने से स्वादिष्ट व्यंजन चखाने के बजाए राशि अनाथालयों में भिजवा दी। सरकारी कोष के बजाय सारी रकम डॉ. कलाम ने जेब से भरी। अब हाल यह है कि हमारे सर्वहारा रामदास आठवले ने मुंबई के हज हाउस में इफ्तार की दावत दी। निमंत्रण बांटे। अध्यक्ष मंत्रीजी खुद। दिल्ली से मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और अमजेर शरीफ दरगाह से मुख्य खादिम बुलाए। हज हाउस में पत्रकारों से बातचीत निबटा ली। राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे राम यानी रामनाथ कोविंद का प्रचार कर डाला। इसे कहते हैं- हर्र लगे न फिटकरी। रंग चोखा।

अमित की मिठास

एक तो बाबा। दूसरे योगी और तीसरे रामदेव। उनके कहे पर कौन भरोसा न करेगा? बाबा ने बताया कि भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने 20 किलो वजन घटाया है। योग से या पतंजलि उत्पाद से? बाबा जानें। हम बस इतना जानते हैं कि अमित शाह अब मधुमेह तक से नहीं डरते। पत्रकारों को दावत पर बुलाया। उनके साथ पकवानों का स्वाद लिया। मिष्ठान्न छोड़ नहीं सकते थे। दाल तक को मीठा कर खाने की आदत है। आव देखा न ताव। अमित भाई ने सहायक को इशारा किया। प्यार किया तो डरना क्या? वाली अदा में वहीं मधुमेह रोकने वाली सुई खुद लगाई। मोदी हिदायत के बावजूद कुछ पत्रकार सवाल पूछने से बाज नहीं आते। उनसे पहले मुंह में रसोगुल्ला जा पहुंचा।

> दो गुटों की खींचतान में नतीजा घोषित नहीं किया जा सका है। एक तरफ कानून का बाहुबली है दूसरी तरफ संस्कृति की महारानी। बोहरा वापस लौटे तो युद्ध विराम हो जाएगा। दोनों गुट उन्हें कप्तानी की कमान सौंप देंगे।

निर्विवाद वोहरा

न प्रधानमंत्री तय कर सके और न महबूबा फैसला कर सकी हैं कि कि 81 वर्षीय नरेन्द्र नाथ वोहरा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने रहें या दिल्ली प्रस्थान करें? रही बात पूर्व केन्द्रीय गृह सचिव एन एन वोहरा की। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली वापसी हुई तब नामी क्लब का गतिरोध समाप्त हो जाएगा। बुद्धिजीवियों, राजनीतिकों और संस्कृतिकर्मियों का अड्डा है यह क्लब। क्लब के नए पदाधिकारियों के लिए चुनाव महीनों पहले हुआ। दो गुटों की खींचतान में नतीजा घोषित नहीं किया जा सका है। एक तरफ कानून का बाहुबली है दूसरी तरफ संस्कृति की महारानी। बोहरा वापस लौटे तो युद्ध विराम हो जाएगा। दोनों गुट उन्हें कप्तानी की कमान सौंप देंगे।

रजनी का परिवार

फिल्मी हस्तियों को पार्टी में शामिल कराने वाले नेता रजनी कांत का जलवा जानते हैं। नई पार्टी बनाई तो फिल्म कलाकारों की टोली गिनने वाले थक जाएंगे। रजनी भाड़े के टट्टू नहीं पालते।कोलावरी गाने वाले रांझणा फिल्म केनायक धनुष दामाद हैं। पत्नी लता की बहिन तमिल अभिनेता महेन्द्रन को ब्याही है। हमज़ुल्फ यानी साढू महेन्द्रन की मां विजया वरिष्ठ निर्माता अभिनेता बालाजी की बहिन हैं। मलयालम सुपरस्टार मोहन लाल रजनी के साढू लगते हैं। पूरा बखान नहीं कर सकते। इतना बता दें कि बीते वक्त के अभिनेता शिवाजी गणेशन ने विवाहिता पत्नी से हुई बेटी का नाम विजया रखा और प्रियतमा की बेटी हिंदी फिल्मों की सदाबहार अभिनेत्री रेखा है।

(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

पत्रकारों की गिरफ्तारी का कर्नाटक विधानसभा का प्रस्ताव विशेषाधिकार है या अधिकार का दुरुपयोग?

कर्नाटक विधानसभा ने पिछले हफ्ते दो पत्रकारों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें एक साल की सजा का प्रस्ताव पारित किया है। कन्नड़ पत्रिका हाय बेंगलुरू के संपादक रवि बेलागेरे और येलहांका वॉयस के संपादक अनिल राज पर कुछ विधायकों के बारे में अपमानजनक लेख लिखने का आरोप है। इसी आधार पर विशेषाधिकार समिति ने इन दोनों पत्रकारों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मान लिया है।

संविधान विधायिका को, इस मामले में विधानसभा को सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव के लिए कुछ विशेषाधिकार देता है। साथ ही इनका मकसद विधायकों को किसी दबाव या बाहरी प्रभाव से बचाना होता है, ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके।

कर्नाटक विधानसभा ने सदन या कुछ सदस्यों की छवि बचाने के नाम पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित किया है और दुर्भाग्य की बात है कि यह इस कार्रवाई के लिए कोई तार्किक कारण नहीं है। जनप्रतिनिधियों को आलोचना से बचाने के लिए इस व्यवस्था के तहत कार्रवाई हमेशा ही सवालों के घेरे में आती है, क्योंकि इसे किसी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल जब तक सदन के विशेषाधिकार के मामले में कोई कानूनी संहिता या स्पष्ट नियम-कायदे नहीं बनते, तब तक पत्रकारों को तो छोड़िए, किसी के भी खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता। यह कार्रवाई तभी जायज ठहराई जा सकती है जब सदन की कार्रवाई या सदन के सदस्यों के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की जा रही हो।

रवि बेलागेरे और अनिल राज के 2014 में लिखे इन आलेखों के बारे में तीन विधायकों ने शिकायत की थी। इस मामले में यह कोई मुद्दा ही नहीं है कि आलेखों में इन विधायकों की आलोचना सही थी कि नहीं। यहां बस यह ध्यान रखा जाना चाहिए था कि इन आलेखों की वजह से विधायकों के स्वतंत्र कामकाज में कोई बाधा

द हिंदू का संपादकीय

नहीं आ रही थी। और अगर विधायकों को ऐसा लगा था कि इन आलेखों की वजह से उनका अपमान हुआ है तो वे निजी तौर पर मानहानि का मुकदमा कर सकते थे।

अगर सदन की स्वतंत्र कार्रवाई में कोई बाधा डालने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल आलोचकों को चुप कराने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आलोचना गलत है तो सदन के सदस्य सही तथ्यों को जनता के सामने लाने की स्थिति में तो होते ही हैं। इस लिहाज से उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वे विशेषाधिकार हनन के मामले में कारावास की सजा की मांग करें।

सदन के पास विशेषाधिकार हनन के मामले में किस तरह के अधिकार होने चाहिए, यह पूरा मुद्दा सवालों के घेरे में है। कोई संहिता न होने की वजह से यह पूरी तरह सदन पर निर्भर करता है कि वह जिस मामले को चाहे विशेषाधिकार हनन का मामला बता दे। मान लेते हैं कि सदन को ऐसे अधिकार हैं, तब भी यह सवाल तो उठता ही है कि क्या सदन विशेषाधिकार समिति के जरिए अपने ही मामले में न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है। और यह भी कि विशेषाधिकार हनन के मामले में क्या सदन किसी को कारावास की सजा सुना सकता है।

कुछ मिलाकर वह समय आ गया है जब विधायिका विशेषाधिकार के मामले में संहिता बनाए और न्यायपालिका तय करे कि विशेषाधिकार हनन होने पर संबंधित समिति क्या-क्या सजा सुना सकती है। फिलहाल कर्नाटक सरकार को यह बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर इस मामले में कार्रवाई होती है तो उसे जनता की आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के पास अभी-भी मौका है। वे आगे आकर इस प्रस्ताव को रद्द करवा सकते हैं और इस तरह सदन की छवि को दाग लगने से बचा सकते हैं। *(सत्याग्रह)*

काँव-काँव

■ हिंदुस्तानी उपग्रह पाक सरहद पर नजर रखने वाला है...

■■ भारत के भीतर के भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाला उपग्रह भी बने तो कोई बात हो...

चौपाल

बंटवारा

जब मैं छोटा सा था तब मैंने पहला बंटवारा देखा, मेरे पिता और चाचा ताऊ में बंटवारा हुआ और हमारा परिवार जॉइंट फैमिली से टूटकर एकल परिवार रह गया । हम सभी छोटे बच्चों को दुख था लेकिन हमारे बस से सब बाहर था। हमारी दादी व दादा खूब रोए थे। खुश थे तो हमारे माता-पिता, चाचा-चाची, ताऊ-ताई। फिर मैं बड़ा हुआ, तो मेरे भाइयों के साथ मैंने बंटवारा किया, अबकी बार बंटवारा हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे और ये सोचकर खुश थे कि अकेले अपना अपना जीवन जियेंगे तो खुश रहेंगे। अब दुखी कौन था, हमारे बच्चे व हमारे वो माता-पिता जिन्होंने पहले बंटवारा करके समझ लिया था कि कितनी बड़ी भुल थी उनकी ।

आज मैं दादा बन गया हूँ, आज मैं अपने जीवन का तीसरा बंटवारा देख रहा हूँ, आज मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब वे पैसों को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर वैसे ही झगड़ रहे हैं जैसे कभी मेरे पिता, जैसे कभी मैं झगड़ा था अपने भाइयों से। आज एक बात का और एहसास हुआ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे कि कब ये बुड्ढा मरे और हम जमीन जायदाद बेचकर अपनी अलग जिंदगी जियें।

पूरा जीवन इन्हीं मूर्खताओं में लग गया।

क्यों होता है आखिर ये बंटवारा ?

एक घर मे रहते हुए हम एक क्यों नही होते ?

असल में घर में सबसे बड़ा झगड़ा है चालेगी किसकी। समझदार कोई भी नही है, सब मनमानी व मनमर्जी थोपते हैं एक-दूसरे पर। बड़े हैं तो समझदार हो गए, ऐसी मान्यता होती है। मैं ज्यादा कमाता हूँ, मेरी क्यों नही चलेगी। मैं बलशाली हूँ, मेरी चलेगी। रूप बल धन पद से हमारी पहचान है, सम्मान है ।

जिनकी दृष्टि में प्रिय हित व लाभ ही सब कुछ होता है, उन्हें साधन व सुविधा ही अच्छा लगता है। हम दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष करने लगते हैं चाहे वो अपना ही भाई क्यों न हो । जिनकी दृष्टि में सत्य, न्याय, व धर्म बड़ा होता है, वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को स्वीकार कर पाते हैं और ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। परिवार के सभी व्यक्ति की ऐसी दृष्टि उसके अंत समय मे आ ही जाती है, लेकिन अब उसकी सुनता कौन है, आखिर बुड्ढा भी कभी जवान था । आज यदि हम सभी इस दृष्टि को प्राप्त कर लें (शिक्षा व्यवस्था में) या कुछ दिन के पारिवारिक शिविर में तो हम इन बंटवारों से बच सकते हैं । ये निर्णय सदा की तरह आज की जवान पीढ़ी को लेना है क्योंकि अगला बंटवारा वो ही करने वाला है । अपने बुजुर्गों से पूछिए कि क्या पाया उन्होंने बंटवारा करके। यह बंटवारे मानव के द्वारा उसके परिवार में ही नहीं हुए, समाज में भी हुए, गांव में, राज्य में, देश में । यही झगड़े के कारण हैं, यही युद्ध के कारण हैं। आतंकवाद, विद्रोह भी इसी बंटवारे से जन्मा है ।

-पी के पांडेय *(व्हाट्सऐप पोस्ट)*

'हिंदी' का सम्मान हो

सबने हिंदी सिखनी चाहिए यह केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की बात को ट्वीट कर जवाब देते कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हिंदी अपनी राष्ट्र भाषा नहीं है। वह भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा होने के कारण उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसको जबरदस्ती किसी पर लादना नहीं चाहिए। हिंदी का नाम लेते ही कुछ लोगों को दिल से अच्छा नहीं लगता। हमेशा अंग्रेजी का ढिंढोरा पिटने वालों को मानो उसकी एलर्जी हो। हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए कुछ न करने वाले उसका प्रचार-प्रसार रोकने के लिए कैसे उतावले होते है, उसका उदहारण उनके एक ट्वीट से देखने मिला। जो भाषा देश में सब से अधिक बोली जाती है वह बोलने में क्यों शरमाए?

हिंदी भले ही राष्ट्र भाषा नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल तो राष्ट्र भाषा की तरह ही देश में किया जाता है। देश की मुख्य भाषा का प्रचार रोकने वाले ही उस के दुश्मन होते है। 'सिर्फ काम के लिए अंग्रेजी सिखना जरुरी है', यह कहते कहते उस भाषा ने पूरे देश पर जबरदस्ती से कब्ज़ा कर लिया है। इस जबरदस्ती पर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना भारी प्रभाव अंग्रेजी का बढ़ गया है। एक-दूसरे देश की भाषा अपने देश में आती है और उसका उपयोग स्कूल से व्यापार, नौकरी में बड़ी मात्रा में आसानी से होता है।

क्या यह हमारे लिए गर्व की बात है? इस कारण कई छात्र पीछे रह जाते हैं। उन्हें देश के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल बढ़ना बहुत जरुरी है। उसकी शुरुआत पढ़ाई के माध्यम से कैसे की जा सकती है, उस पर विचार करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा करके तो देखिए देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते ही जाएगा। चीन, जापान अपनी भाषाओं का इस्तेमाल शिक्षा सहित कारोबार में करते हैं और उसका नतीजा क्या है वह पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा बदलाव लाने की दिल से इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का बच्चा बच्चा देश की प्रगति के लिए अपना योगदान प्रदान करने के लिए तैयार रहेगा।

- जयेश राणे, मुंबई

जवाबदेही तय हो

कोरिया ज़िले में हुई पहली हल्की बारिश में हाल ही में निर्मित स्टेडियम का एक हिस्सा बह गया। इसके अलावा आधे से ज्यादा मैदान भी धंस गया। वही जिला प्रशासन स्टेडियम को दुरुस्त करने की बात कह रहा है, जबकि गुणवत्ताहीन निर्माण पर चुप्पी साधे हुए है। इस तरह के हालात प्रदेश में कई जगह अन्य निर्माण कार्यों में भी देखने को मिलते हैं। जब तक जवाबदेह अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती तब तक दोष एक-दूसरे पर मढ़ने का क्रम चलता रहेगा। नतीजा सिफर रहेगा और भ्रष्टाचार होता रहेगा।

-परसराम देवांगन, दुर्ग

सुनो बटोही

भ्रष्टाचार
चारों खाने चित्त है... !!
क्योंकि इसमें
भ्रष्टाचार
उन्मूलन प्रकोष्ठ
के सदस्य ही
संलिप्त हैं... !!

-श्रीराम साहू बसना, महासमुंद

दिल से

you will search for me in another person. I promise.

You're the prettiest causality of my life.

I would sacrifiñå anything come what might for the sàke of hàving you naar.